3 एमएसपी की मौजूदा व्यवस्था में सुधार करें

5 सुशासन से बनाई विशिष्ट पहचान

5 PM ने नदियों को जोड़ने की आधारशिला रखी

RNI-MPBIL/2011/39805

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 15 अंक : 33 प्रति सोमवार, 23 दिसंबर 2024 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

क्या उज्जैन के भू-माफिया को बना दिया मोदी जी ने मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री?

आखिर बंशीलाल राठौर एवं उनकी पत्नी कृष्णा राठौर को मुख्यमंत्री मोहन यादव के अत्याचार से कौन बचाएगा?

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
संपादक

आज जब देश में लोकसभा और राज्यसभा में नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा संविधान दिवस को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मना रही है और उसके गौरव को लेकर "संविधान पर चर्चा की जा रही है" उसके ठीक उलट नरेन्द्र मोदी द्वारा बनाये नये मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश में असंवैधानिक कार्य में लगे हुए हैं। प्रदेश में किसी भी मजलूम पर हुए अत्याचार पर न्याय दिलाने की जिम्मेदारी प्रदेश के मुखिया अर्थात मुख्यमंत्री पर होती है पर उसके ठीक उलट मप्र के मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद गरीबों की जमीन हड़प कर उनको जेल भिजवाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश की विडंबना है कि आज सरकार के एक साल पूरे होने के बाद स्वयं मुख्यमंत्री और उनके परिवार उज्जैन क्षेत्र में भू-माफिया जैसा व्यवहार कर रहे हैं। इसके एक उदाहरण बंशीलाल राठौर है। दरअसल बंशीलाल के पूर्वजों की जमीन जो कि तीन बत्ती चौराहे के पास करीब पांच बीघा थी उसकी फर्जी रजिस्ट्री, नामांतरण और मूल दस्तावेज गायब करवाकर करोड़ों-अरबों रूपयों का एसएन कृष्णा अस्पताल खोला गया। इसके साथ ही प्रशासन का दुरूपयोग कर मूल जमीन के मालिक को जेल करवा दी एवं उसके परिवार का हुक्का पानी तक बंद करवा दिया।

मुख्यमंत्री के अत्याचार से पीड़ित बंशीलाल राठौर की पत्नि कृष्णा राठौर ने सुनाई अपनी व्यथा

"आज से चार पांच साल पहले कोरोनाकाल के समय जब मुख्यमंत्री मोहन यादव शिवराज सरकार में शिक्षामंत्री थे। उन्होंने उज्जैन में मेरी जमीन हड़प ली। वह लोगों के कार्नर की जमीनों को भी हड़पते हैं। मेरे पति को बार-बार झूठे केस में जेल में डाल देते हैं। मैं बोलती हू कि मेरा सबकुछ ले लो लेकिन मुझे छोड़ दो। मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव के अत्याचार से पीड़ित हूं। चक्की चलाकर गुजारा करती हूं। एवं बार-बार तंग करने के लिए जल्दी-जल्दी आठ-आठ दिन में पेशी कराई जाती है। जिससे मेरी रोजी रोटी बंद हो जाये। (शेष पेज 2 पर)

छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा की लापरवाही और उदासीनता से चरमरा गई प्रदेश की कानून व्यवस्था

गृहमंत्री विजय शर्मा के कारण मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार को विधानसभा में होना पड़ा लज्जित

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया है। विधानसभा सत्र के दौरान विपक्षी दल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के एक वर्ष का लेखाजोखा जनता के सामने रखने की मांग की। खास बात यह है कि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनकल्याण और जनहित में लिये गये निर्णयों की विस्तृत जानकारी विधानसभा पटल पर रखी। (शेष पेज 3 पर)

आखिर मध्यप्रदेश में लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के कारण 3 हजार से अधिक लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है?

विभाग ने 45 हजार करोड़ के उपकरण खरीदे, फिर भी दवा के अभाव में जान गंवाने को मजबूर हुई प्रदेश की निर्दोष जनता

-विजया पाठक

खुद को गरीबों का मसीहा और जनता का हितैषी बताने वाली मध्यप्रदेश भाजपा सरकार की करतूतों से परते खुलना आरंभ हो गया है। राज्य की जनता के बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था और सुविधा प्रदान करने संबंधी बड़ी-बड़ी बातें करने वाली भाजपा सरकार द्वारा जनता के लिये की गई व्यवस्थाओं से कैग की रिपोर्ट ने परदा हटा दिया। परदा हटते ही सरकार द्वारा जनता के हितों को साधने और बेहतर स्वास्थ्य के लिये किये जाने वाले तमाम वायदों की पोल खुलना शुरू हो गई है। जाहिर है कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्षी दल ने पटल पर पेश हुई कैग की रिपोर्ट में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और इलाज से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद जबरदस्त हंगामा किया। कैग की रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रदेश के 10 मेडिकल कॉलेज में आईसीयू में भर्ती 34,643 में से 3,025 मरीजों की मौत हो गई। अगर प्रतिशत देखें तो 16,848 (48.64%) श्वास और हृदय रोग से संबंधित थे। इनमें से 3,025 (18%) मरीजों की मौत हो गई। (शेष पेज 2 पर)

स्पेशल खबर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रयासों से नवा रायपुर बनेगा भविष्य का शहर

109 करोड़ रूपए की लागत से बिछाई जाएगी 16 किमी लंबी पाइपलाइन

(विस्तृत पेज 2 पर)

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रयासों से नवा रायपुर बनेगा भविष्य का शहर

-शशि पाण्डेय

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रयासों से नवा रायपुर अटल नगर अत्याधुनिक सुविधाओं वाला शहर बनने की तरफ अग्रसर है। राज्य के आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने नवा रायपुर अटल नगर को देश के आधुनिक शहरों में शुमार करने के लिए इसे भविष्य के शहर के रूप मे तैयार करने हेतु प्रयासरत हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक है आने वाले 25 वर्षों तक नवा रायपुर अटल नगर के लोगों को लिए निर्बाध पेयजल की सप्लाई। भविष्य में भूमिगत जल में कमी और बढ़ती जनसंख्या की मांग के अनुसार पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नवा रायपुर विकास प्राधिकरण ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए अभनपुर के पास कोड़ापार से थनौद टीला एनीकट तक एक नई पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह पाइप लाइन 16 किमी लंबी होगी और इसकी अनुमानित लागत लगभग 109 करोड़ रूपए होगी। नवा रायपुर अटल नगर में टीला एनीकट से पानी की सप्लाई होती है। लेकिन गर्मी के दिनों में पानी की कमी होने से एक प्राकृतिक खुली नहर के द्वारा कोड़ापार से थनौद तक पानी की आपूर्ति की जाती है। कोड़ापार तक पानी रविशंकर जलाशय से आता है। कोड़ापार से थनौद तक खुली नहर की दूरी लगभग 25 किमी है। इतनी लंबी दूरी तक

खुली नहर के माध्यम से छोड़ने पर काफी मात्रा में पानी का नुकसान हो जाता है। खुली नहर की वजह से पानी की वास्तविक क्षमता का इस्तेमाल नहीं हो पाता है। नवा रायपुर के लोगों को पानी की दिक्कत न हो और साथ ही पानी का नुकसान भी न हो इसके लिए प्राकृतिक नहर के स्थान पर पाईपलाइन के माध्यम से नहर का पानी नया रायपुर अटल नगर तक पहुंचाया जायेगा। पाइप लाइन बिछाने से कोड़ापार से थनौद तक की दूरी भी कम होगी और बिना किसी नुकसान से अपनी वास्तविक क्षमता में पानी थनौद तक पहुंचेगा। इस परियोजना के अमल में आने और पूर्ण हो जाने से भविष्य में शहर के नागरिकों को पेयजल से जुड़ी किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।

क्या उज्जैन के भू-माफिया को बना दिया मोदी जी ने मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री ?

(पेज 1 से जारी)

पूर्व टीआई तरून कुरील (थाना नीलगंगा उज्जैन) जो कि मोहन यादव का स्कूल मित्र है। वह मुझे डराता, धमकाता है। टीआई भी इनसे मिला है। बिना पढ़े कागजों पर दस्तखत करवाता है। एक लाख रूपये मांगता है। एसआई बड़ोनिया के साथ मिलकर आये दिन मुझे तंग करते हैं। पैसों की मांग करते हैं। मैं हर रोज के कोर्ट कचहरी से परेशान हो गई हूं। यह जमीन मेरी पुश्तैनी है। मेरे पति इस संपत्ति के इकलौते वारिस हैं। अभी भी मेरे पति को झूठे 420 के केस में जेल में बंद कर दिया है। आज जब मैं आपसे (विजया पाठक) मिलने आ रही थी तब किसी अज्ञात मोटर साईकिल वाले ने मुझे धक्का मारा जिससे मेरे सिर में चोट आई है और मैं बाल-बाल बच गई। मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं परिवार सहित आत्महत्या कर लूंगी।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में जमीनें हड़पकर बनाया साम्राज्य

ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव पर कृष्णा राठौर ने जमीन घोटाले का आरोप लगाया है। इससे पहले भी सिंहस्थ जमीन घोटाला हुआ था जिसमें मोहन यादव का नाम सामने आया था।

पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के हस्तक्षेप के बाद मामला रफा-दफा हुआ था। इनकी पार्टी के पूर्व मंत्री पारस जैन ने खुद मोहन यादव पर आरोप लगाये थे। महाकाल की नगरी के जमीन घोटाले में मोहन यादव का नाम अक्सर आता है। कृष्णा राठौर के मामले में न्याय मिलना चाहिए, इस मामले में भाजपा आलाकमान भी हस्तक्षेप करें ताकि उज्जैन में हो रहे जमीन घोटालों पर कुछ हद तक लगाम लग सके। सूत्रों का कहना है कि उज्जैन में कोई भी बिल्डर काम नहीं करना चाहता है क्योंकि बिल्डर्स को डर लगा रहता है कि कहीं यह विवादित जमीन तो नहीं है। वहीं प्रशासन भी निरंकुश बना हुआ है। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी ऐसे मामलों में हाथ नहीं डालना चाहता है और लोगों की सुनवाई तक नहीं करते हैं। पुलिस का खौफ भी इतना है कि कई मामलों को वह खुद ही निपटा देते हैं।

कैसे आलाकमान के आशीर्वाद से बने मुख्यमंत्री बने मोहन यादव

कोई सवा साल पहले किसी को बिल्कुल भनक भी नहीं थी कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। सुरेश सोनी ने संघ की तरफ से और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोहन यादव का नाम नरेंद्र मोदी के सामने रखा और उनका मुख्यमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। बड़ा सवाल यह है क्या नरेंद्र मोदी और आलाकमान के सामने ऐसे मामलों को सामने रखा गया था कि नहीं और अगर मोहन यादव और उनके परिवार, समर्थकों की 700-800 बीघा और ना जाने कितनी संपति 2003 के बाद कैसे बनी, क्या इसकी जांच पड़ताल की गई थी। अगर आलाकमान इस मामले को संज्ञान में नहीं लाएगी तो निश्चित तौर पर आलाकमान को यदुरप्पा जैसी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। निश्चित तौर पर एक मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले देश में नरेंद्र मोदी की साख में बट्टा जरूर लगाएगी।

आखिर मध्यप्रदेश में लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के कारण 3 हजार से अधिक लोगों मौत का जिम्मेदार कौन है ?

(पेज 1 से जारी)

प्रदेश सरकार भले ही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बेहतर होने के दावे कर रही हो, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि पांच सालों में मध्य प्रदेश में 45,324 करोड़ स्वास्थ्य पर खर्च होने के बावजूद सांस-हृदय की बीमारियों के इलाज के लिए 16 महत्वपूर्ण दवाओं में से 11 मरीजों को नहीं मिलीं। इसी तरह कार्डियोवैस्कुलर समस्याओं के उपचार के लिए 26 महत्वपूर्ण दवाएं नहीं थीं। रिपोर्ट में सामने आया है कि अति महत्वपूर्ण ईडीएल 448 दवाओं का स्टाक नहीं पाया गया. यही नहीं और चिंता की बात तो यह है कि भोपाल के हमीदिया अस्पताल, जेएएच ग्वालियर और सिम्स छिंदवाड़ा में तो 1.11 करोड़ की 263 दवाएं एक्पायर हो गई।

कौन लेगा इलाज के अभाव में जिंदगी गंवाने वाले लोगों की जिम्मेदारी

एक तरफ जहां प्रदेश सरकार अपने एक वर्ष पूरे होने का जश्न जोरो-शोरो पर मना रही है। उत्सव के तौर पर लाखों करोड़ों रुपये खर्च किये जा रहे हैं। वहीं अगर उत्सव मनाने के बजाय भाजपा और डॉ. मोहन यादव की सरकार ने जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्थाएं की होती तो शायद आज आंकड़ें कुछ और होते। लेकिन प्रदेश सरकार की उदासीनता और स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली तथा लापरवाही से हजारों लोगों को अपनी जिंदगी गंवाना पड़ी। बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा, क्या मोहन सरकार इन मौतों की जिम्मेदारी लेगी या फिर कोई आईएएस अधिकारी इस मामले पर बली का बकरा बनेगा जिस पर जांच के नाम पर कार्यवाई की जायेगी।

आखिर किया क्या सारंग ने चिकित्सा मंत्री रहते हुये

मध्यप्रदेश में भले ही कैग की रिपोर्ट विधानसभा में आज सामने आई हो, लेकिन यह आंकड़ें उस समय के बताये जा रहे हैं जब प्रदेश में भाजपा की ही सरकार थी और प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा की जिम्मेदारी भ्रष्टाचारी विश्वास सारंग पर थी। सारंग ने तत्कालीन अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान के साथ सांठगांठ कर न सिर्फ प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई और बल्कि मेडिकल कॉलेजों में किये जाने वाले बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की भी ऐसी तैसी कर दी। सारंग ने करोड़ों रुपये मेडिकल उपकरण खरीदने के नाम पर खाये और चिकित्सा शिक्षा विभाग में जमकर भ्रष्टाचार किया। सारंग द्वारा किये गये भ्रष्टाचार का धुआं इतना तेज था कि उसके अवशेष राज्य के हर कोने में पहुंचे और प्रदेश की पूरी की पूरी चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो गई।

सारंग पर आखिर क्यों चुप्पी साधे हैं मुख्यमंत्री ?

कैग की रिपोर्ट के बाद प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। अब तो आमजनता का भी भरोसा प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्री से उठने लगा है। लेकिन एक बात जो आज तक समझ के परे है कि चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था में सारंग द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की तमाम जानकारी सामने आने के बाद और विपक्षी दल द्वारा बार-बार जांच करवाने की मांग को अभी तक मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने क्यों नहीं स्वीकारी है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव सारंग के मामले पर चुप्पी साधे बैठे हुये हैं और कोई भी कार्यवाई करने का फैसला नहीं ले पा रहे हैं।

उपकरणों और दवाओं की खरीद में भी गड़बड़ी

कैग ने न सिर्फ प्रदेश के स्वास्थ्य अधोसरंचना से जुड़े मामलों पर सवाल खड़ा किया है बल्कि कैग द्वारा प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में की गई मेडिकल उपकरण की खरीदी पर भी सवाल पूछा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदेश के 14 स्वास्थ्य संस्थाओं में सीएमएचओ स्टोर में एक करोड़ 20 लाख रुपए कीमत की 201 मशीनें खराब मिलीं। यह उपकरण 9 महीने से 8 महीने की अवधि में किसी भी वार्ड या स्वास्थ्य संस्थान को जारी नहीं किए गए। 263 टेंडर में से 30 टेंडर निविदा प्रकाशन की तारीख से लेकर निगम पोर्टल पर अनुबंध की तारीख से 6 महीने से एक साल तक की देरी हुई। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की जनता के साथ किये गये खिलवाड़ पर विपक्षी दल ने सख्त रुख अपनाते हुये विधानसभा का वॉक आउट किया और निष्पक्ष जांच की मांग की है।

कैग ने 5 सालों की जांच की

कैग ने जिन 5 सालों की जांच की है, उसमें कोरोना का दौर भी शामिल है। डीएमई की जांच में पाया गया कि 2017-2020 और 2021-22 के लिए दवा खरीदी योजना तैयार नहीं की गई। 13 महीने की देरी से यह जानकारी एमपीपीएचएससीएल को भेजी गई।

सारंग पर नर्सिंग घोटाले के भी लगे हैं आरोप

मध्यप्रदेश में व्यापम घोटाले के बाद नर्सिंग घोटाला दूसरा सबसे बड़ा घोटाला है। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने में बड़ी अनियमितता सामने आई। यह अनियमितता पिछली सरकार के कार्यकाल में हुई है। इस दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग थे। प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने में शासन के निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन हुआ। इसमें ऐसे कॉलेजों को मान्यता दी गई जो या कागजों में चल रहे थे या फिर एक कमरे से संचालित हो रहे थे। कई कॉलेज किसी भी अस्पताल से संबंद्ध नहीं थे। इसका खुलासा होने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस पर कोर्ट ने 375 से ज्यादा कॉलेजों की जांच सीबीआई को सौंपी थी।

एमएसपी की मौजूदा व्यवस्था में सुधार किया जाएः विपिन पटैल

-संवाददाता

जगत प्रवाह. गुजरात। एमएसपी किसानों को बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन केवल इससे बेहतर कृषि आय की गारंटी नहीं मिलेगी। जरूरत ऐसी सेवाओं की है जो किसानों की आय वृद्धि में सुधार कर सकें और उन्हें विविधता लाने में मदद कर सकें। यह कहना है सीफा के राष्ट्री य अध्यदक्ष विपिन पटैल का। उन्होंयने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे मूल्य जाने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित फसलों का न्यूनतम विक्रय मूल्य उसी तरह तय किया जाये, जिस तरह केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप धारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चीनी मूल्य (नियंत्रण) आदेश, 2018 अधिसूचित कर चीनी का न्यूनतम विक्रय मूल्य तय किया था। भारत में सीमांत और छोटे किसान, या तो बेचने के लिए कोई उपज नहीं रखते या बहुत कम अधिशेष रखते हैं। इसलिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए C2 के साथ ही अन्य उपाय करने होंगे। जैसे मुख्य फल-सब्जी, दूध व उसके अन्य उत्पाद का न्यूनतम बिक्री मूल्य तय करना, ग्रामीण उद्योग व वैल्यू एडिड उद्योग को बढ़ावा देना व उनके उत्पाद की गुणवंता बढ़ाने के साथ उनकी बिक्री की व्यवस्था करना आदि। (जगत फीचर्स)

विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर ध्यान कार्यक्रम का आयोजन

भरत मुनि सम्मान से सम्मानित हुए सूर्य कृष्णमूर्ति

-अमित राय

जगत प्रवाह. भुवनेश्वर। ओडिशा की पुरानी ओडिसी नृत्य अनुष्ठान कलिंगायन त्योत्रिक्रम नृत्य अनुष्ठान की तरफ से आयोजित 15वीं भरत मुनि सम्मान समारोह सम्पन्न हुआ। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर स्थित रविन्द्र मंडप में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। दो दिवसीय कार्यक्रम 16 तथा 17 दिसंबर को आयोजित हुआ। 15वें भरत मुनि सम्मान समारोह के अंतिम दिन भरत मुनि सम्मान से विशिष्ट निदेशक, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त सूर्य कृष्णमूर्ति सम्मानित हुए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की रूप में पूर्व राष्ट्रदूत और अनुष्ठान के अध्यक्ष जितेंद्र नाथ मिश्र और पद्मश्री पुरस्कार विजेता, इटालियन ओडिसी नृत्य शिल्पी इलियाना सिटारिस्टी ने पुरस्कार प्रदान किया। इस कार्यक्रम के पहले चरण में सी एच अजय कुमार ने कुचिपुड़ी नृत्य और सूर्यमणि रमेश दास और डॉ शारदा प्रसन्न दास ने जुगलबंदी वायलिन को प्रदर्शित किया। भारत मुनि सम्मान के पूर्व पुरस्कार विजेता में थंकमणि कुट्टी (2008), पंडित बिरजू महाराज (2009), पंडित जसराज (2010), रतन थियाम (2011), हेमामालिनी (2012), पंडित हरि प्रसाद चौरसिया (2013), एसजे रघुनाथ महापात्र (2015), तीजन बाई (2016), डॉ. अडूर गोपाल कृष्णन (2017), डॉ. यामिनी कृष्णमूर्ति (2018), धनंजयंस (2019), एसजे सीताकांत महापात्र (2020), उषा उथुप (2021), स्वप्न सुंदरी (2023) का नाम दर्ज है। (जगत फीचर्स)

8 नक्सली गिरफ्तार, फोर्स को मिली बड़ी सफलता

-संवाददाता

जगत प्रवाह.बीजापुर। बस्तर संभाग में नक्सलियों के खिलाफ लगातार सर्च ऑपरेशन चलाकर नक्सलियों को पकड़ा जा रहा है। बीजापुर में संयुक्त बल ने सर्चिंग के दौरान 8 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत गवर्ना ने इसकी पुष्टि की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सारकेगुड़ा के राजपेटा से 18 दिसंबर को जिला पुलिस बल, केंद्रीय सुरक्षा बल की 210 व 168 बटालियन की टीम बासागुड़ा व नैमेड़ में विशेष अभियान पर निकली थी। तभी जवानों को देखकर 4 संदिग्ध भागने लगे. जवानों ने तीनों को पकड़ा और उनसे पूछताछ की।उनके पास मिले सामान से उनके नक्सली होने की पुष्टि हुई। तलाशी के बाद पुलिस ने नागेश बोड्डुगुल्ला 31वर्ष, मासा हेमला 35वर्ष, सन्नू ओयाम 53 वर्ष व लेकाम छोटु 21वर्ष को गिरफ्तार किया. उनके पास से कुकर बम, टिफिन बम, कार्डेक्स वायर, बिजली तार, दवाईयां व माओवादी साहित्य बरामद किया. चारों किसी नक्सली घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे थे इसी दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। वहीं दूसरे मामले में नैमेड पुलिस ने जनताना सरकार सदस्य शंकर पुनेम 25 वर्ष, बदरु अवलम 38 वर्ष, सन्नू पोयाम 35 वर्ष व कमलू हेमला 34 वर्ष को गिरफ्तार किया है। इन सभी के पास नक्सली विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। बासागुड़ा और नैमेड़ में पकड़े गए सभी नक्सलियों को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद सभी को जेल भेज दिया गया। (जगत फीचर्स)

महतारी वंदना योजनाः महिलाओं की सूझ-बूझ से 14 हजार रूपए एकमुश्त

-आनंद शर्मा

जगत प्रवाह. रायपुर। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के सुभाषनगर में अहिरवार समाज की 14 महिलाओं ने राज्य सरकार की महतारी वंदना योजना के तहत मिलने वाली राशि को सामूहिक बचत और निवेश का माध्यम बनाकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव की मिसाल पेश की है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महतारी वंदना योजना के अंतर्गत, पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन महिलाओं ने व्यक्तिगत खर्चों में इस राशि को उपयोग करने के बजाय, सामूहिक रूप से इसे एकत्रित करने का निर्णय लिया। हर महीने की 5 तारीख को आयोजित बैठक में, वे कुल 14,000 रुपये का फंड बनाती हैं, जिसे जरूरतमंद सदस्य को दिया जाता है। महिलाओं के इस सामूहिक प्रयास के परिणामस्वरूप, सदस्यों ने अपने परिवारों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा किया है। सविता ने अपने पति की जूते की दुकान को बढ़ाने में मदद की। चंद्रिका ने अपने दामाद की बरसी पर होने वाले खर्च को पूरा किया। कोमिन ने अपने घर का प्लास्टर कराया है। नरगिस ने अपनी फैंसी स्टोर को बढ़ाया है। गणेशी ने गंगा दर्शन का अपना सपना पूरा किया। शकीला ने अपनी नातिन को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। ईश्वरी हठीले ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घर में सीढ़ी बनवाई। उत्तरा ने अपनी बेटी की हॉस्टल फीस भरी। रेमा ने गोदरेज की आलमारी खरीदकर अपने परिवार के लिए सुविधा बढ़ाई है। समूह की सदस्य उत्तरा कहती हैं, पहले यह राशि घर के छोटे-मोटे खर्चों में खत्म हो जाती थी। लेकिन जब हमने इसे मिलकर बचाने का निर्णय लिया, तो इसे बड़े कामों में लगाना संभव हो पाया। गणेशी कहती हैं, कोई हमें एक रुपया देने तैयार नहीं था, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने हमें हर महीने 1,000 रुपये देकर ऐसा सहारा दिया, जैसे मायके में पिता और बड़े भाई देते हैं। इस पहल ने महिलाओं को आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता का अनुभव कराया है, साथ ही सामूहिकता की भावना को भी प्रोत्साहित किया है। सुभाषनगर की इन महिलाओं ने साबित किया है कि सही दिशा में छोटा प्रयास भी सफलता की ओर ले जाता है। महतारी वंदना योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना है। महासमुंद की इन महिलाओं का सामूहिक बचत और निवेश का यह मॉडल अन्य समुदायों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है, जिससे वे भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। इस प्रकार, महतारी वंदना योजना ने न केवल व्यक्तिगत स्तर पर महिलाओं की सहायता की है, बल्कि सामूहिक प्रयासों के माध्यम से समुदाय के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महिलाओं की यह पहल इस बात का प्रमाण है कि सरकारी योजनाओं का सही उपयोग और सामूहिकता की भावना मिलकर समाज में व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है। (जगत फीचर्स)

छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा की लापरवाही और उदासीनता से चरमरा गई प्रदेश की कानून व्यवस्था

(पेज 1 से जारी)

वहीं दूसरी विपक्षी दल ने प्रदेश में लचर होती कानून व्यवस्था पर गृहमंत्री विजय शर्मा को घेरा। राज्य के अंदर पिछले एक वर्ष के दौरान जो भी बालात्कार, मर्डर, नकस्ली हमले, अड़बाजी, चोरी, डकैती जैसे कारनामें हुए उन सभी पर विपक्षी दल ने सत्ता पक्ष के गृहमंत्री विजय शर्मा को न सिर्फ कटघरे में खड़ा कर दिया बल्कि उन्होंने साय सरकार की कार्यशैली और गृहमंत्री पर नकेल न कस पाने जैसे गंभीर आरोप लगाये। विधानसभा के पांच दिन के सत्रो के दौरान विपक्षी दलों ने लगभग 100 से अधिक विषयों पर सरकार से जबाव मांगा। यही नहीं प्रदेश में खस्ताहाल होती कानून व्यवस्था पर गृहमंत्री विजय शर्मा के संतोषजनक ढंग से जबाव नहीं देने पर विपक्षी नेताओं ने चुटकी लेते हुए विजय शर्मा के इस्तीफे तक की बात कह दी।

एनकाउंटर में निर्दोष लोगों के मारे जाने का मुद्दा

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने राज्य में नक्सली घटना में आम नागरिकों की मौत का मुद्दा उठाया और गृहमंत्री विजय शर्मा को घेरा। उन्होंने घटनावार जानकारी मांगी. इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने गोल-मटोल जबाव देते हुए कहा कि नक्सलवाद का दंश पूरा प्रदेश झेल रहा है। हमें जानकारी बताने में परेशानी नहीं है. लेकिन, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा. इस बात का आरोप लगाया गया था कि भरमार बंदूक ले जाते हैं और और लोगों को नक्सली बताते हैं। विपक्षी दलों के नेता ने आरोप लगाये कि जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है तब से छत्तीसगढ़ में क्राइम रेट बढ़ा है। प्रदेश में एक सप्ताह के भीतर तीन बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया चुका है। पूरे प्रदेश में अपराध बढ़ रही है। विपक्षी दल के नेताओं ने विधानसभा में कहा कि यह सुशासन नहीं बल्कि जंगल राज है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। अपराधियों को संरक्षण देने का काम सरकार कर रही है।

इन घटनाओं के कारण शर्मसार हुआ छत्तीसगढ़

उल्लेखनीय है कि जब से गृहमंत्री विजय शर्मा के हाथों में राज्य की कमान आई है तब से हत्या की 562 घटनाएं, यौन शोषण के 859 मामले, डकैती के 29, लूट के 215, बलात्कार के 1,576, गांजा तस्करी के 713 और साइबर अपराध के कई मामले सामने आए हैं। आपराधिक मामलों में छत्तीसगढ़ की रैंकिंग बढ़ रही है जिस कारण छत्तीसगढ़ शर्मसार हुआ है। गृहमंत्री विजय शर्मा की नाकामी का सबसे बड़ा प्रणाम है कि राज्य में हत्या, चाकूबाजी, बलात्कार, डकैती, धोखाधड़ी और तस्करी जैसे गंभीर अपराध अब रोजाना की बात हो गई है। यही नहीं राजधानी रायपुर धीरे-धीरे ड्रग तस्करी का अड्डा बनता जा रहा है।

इन विषयों को लेकर भी घिरी साय सरकार

विपक्षी विधायक धर्म जीत सिंह ने अस्पतालों में फायर सेफ्टी सेवाओं में लापरवाही का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में लगातार आग लग रही है। फायर सेफ्टी का पालन नहीं हो रहा। इसका क्या इंतजाम है। 2000 में फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट बाजार में बिक रहा है। फायर सेफ्टी के मापदंड में कितने अस्पताल आते हैं। इस पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि फायर सेफ्टी की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की नहीं है, गृह विभाग की जिम्मेदारी है। प्रदेश में नर्सिंग होम एक्ट में पंजीकृत गैर शासकीय अस्पतालों की संख्या 1119 है। फायर ऑडिट गृह विभाग के अंतर्गत आता है। अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन से पहले उनसे एनओसी लेनी होती है। विधायक राजेश मूणत ने सवाल किया कि हमर क्लीनिक बना है तो उसके मेंटिनेंस की जिम्मेदारी किसकी है। क्या योजना आगे चलती रहेगी या नहीं, ये स्पष्ट करें। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जयसवाल ने कहा कि शहर में हमर अस्पताल और गांव में हमर क्लीनिक की योजना है। इसके लिए 338 करोड़ रुपये बजट दिया गया, लेकिन राशि आहरित नहीं कर सके। इसके लिए केंद्र ने 7 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया।

सरकार पर ये भी लगा आरोप

जायसवाल ने कहा कि अनुपूरक में प्राविधान कराकर इस हफ्ते बजट की व्यवस्था कर देंगे। भारत सरकार से दूसरी किस्त भी आएगी। फिलहाल 364 में से 180 संस्थाएं संचालित है, बाकी भी संचालित होंगी। राजेश मूणत ने पूछा कि इस योजना में राज्य की क्या भूमिका है. इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सेटअप में मेडिकल ऑफिसर समेत पांच तरह की सेवाएं हैं। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत संचालित होते हैं. इनके लिए जहां-जहां बिल्डिंग मिल गई वहां संचालित किया गया. जबकि, जहां बिल्डिंग नहीं है, वहां संचालित नहीं हो सकी।

सम्पादकीय

दस वर्षों के शासनकाल में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखा मजबूती से पक्ष

विश्व के तीन बड़े देश के राष्ट्र प्रमुख जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन और अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतकर आए डोनाल्ड तीनों ही राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित राजनेता हैं। जहां नरेंद्र मोदी विगत 10 वर्षों से अधिक समय से भारत के अजेय प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र सेवा कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बड़ी बेबाकी से भारत का पक्ष रखा है। देश के अंदर आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक मसलों का कुशलतापूर्वक समाधान निकाला है। कश्मीर की अनुच्छेद 370 व धारा 35 को हटाना, भारत की आत्मनिर्भरता, देश की अधोसंरचना ठीक करना हो, भारत की सीमाओं का हल निकलना हो, भारत की सेना को और सशक्त बनाने जैसे मामलों ने प्रधानमंत्री मोदी को एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया है। दूसरे वैश्विक नेता के रूप में उभरे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2002 से लेकर लगभग 22 वर्षों तक लगातार रूस के प्रधानमंत्री व फिर राष्ट्रपति के रूप में रूस को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सोवियत संघ के बिखराव के बाद जिस तरह रूस उन्होंने स्थिरता व मजबूती दी, उससे अंतर्राष्ट्रीय जगत में उनका कद बढ़ा। पुतिन की दृढ़ता उन्हें इसी बात पर औरों से अलग करती है। और यही बात उन्हें विश्व के शीर्ष नेताओं के साथ खड़ा करती है जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उन्होंने चुनाव के समय अपने कई सार्वजनिक भाषणों में राष्ट्र के प्रति श्रद्धा एवं समर्पण की बात कही है। आने वाले समय में विश्व के हर एक चुनौती का सामना कर पाने में यह तीनों नेता सक्षम है। अगर इन तीनों वैश्विक नेताओं की तिकड़ी एक दिशा में साथ मिलकर काम करने की रणनीति पर अमल कर लें तो आने वाले समय पर विश्व को एक नई दिशा मिल सकती है।

जो बाइडन के जाते-जाते भारत और अमेरिका के संबंध अपने न्यूनतम स्तर तक पहुंच गए हैं। पिछले दो-तीन दशकों में भारत और अमेरिका के बीच बहुत करीबियां आई थीं, सामरिक मुद्दों के समाधान के लिए दोनों के बीच बेहतर समन्वय व साझा रणनीति भी बनी थी। क्वॉड बना था वह इसलिए क्योंकि दोनों के सामने एक ही चुनौती थी और वह थी कम्युनिस्ट चीन जिनकी आर्थिक ताकत जिसकी सैन्य ताकत दिन दूनी बढ़ रही थी और वह एक बड़ी थ्रेड बनकर उभर रहा था न सिर्फ एशिया के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए लेकिन इस कारण भारत और अमेरिकी संबंधों में निकटता आई। भारत ने अमेरिका से 17-18 बिलियन डॉलर के हथियार खरीदे थे। सी-17 ग्लोबमास्टर, चुनुक अपाचे हेलीकॉप्टर, लांग रेंज फेयर, ड्रोन इत्यादि लेकिन जो बाइडेन के आने के बाद जो अमेरिका के साथ राजनीतिक संबंध थे, उसमें परिवर्तन आया। अमेरिका की दिलचस्पी एशिया की तरफ थी, वो अब यूरोप की तरफ शिफ्ट को गई। अमेरिकी रणनीतिकारों ने अपनी पूरी ताकत चीन की तरफ से हटाकर रूस की ओर लगा दी। इसी रणनीति के तहत अमेरिका ने यूक्रेन को प्यादा बनाकर उसे रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया, ताकि स्य को अलग-थलग किया जा सके। ऐसे में जब भारत ने रूस से कच्चा तेल सस्ते रेट पर अपनी शर्तों पर लेना शुरू किया तो जो बाइडन ने आंखें तरेरीं। रूस-भारत की निकटता को देख बाइडन और अमेरिका को गहरा झटका लगा यही तनाव डेमोक्रेट्स और जो बाइडन को सताता रहा, जिससे अमेरिका और भारत के रिश्तों में खटाश आई। यूक्रेन के अलावा अमेरिका ने बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता पैदा की। वहां शेख हसीना सरकार को धराशायी कराकर अपने पिट्ठू मोहम्मद युनुस को सरकार का प्रमुख बनवाया। अब जब ट्रंप की अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में वापसी हुई है और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आपसी समझ रही है तो दुनियाभर में कयासबाजी है कि आने वाले समय में ये तिकड़ी वैश्विक राजनीति की दिशा बदलने में सक्षम है।

सियासी गहमागहमी

जब लंबे समय बाद मंच पर दिखे सुलेमान

प्रदेश के प्रभावशील आईएएस अधिकारियों में शामिल मोहम्मद सुलेमान लंबे समय बाद मंच पर दिखाई दिए। नर्सिंग घोटाले से लेकर मेडिकल उपकरण की खरीदी में भ्रष्टाचार में घिरे सुलेमान को मोहन यादव की सरकार में हाशिए पर रख दिया है। यही कारण है कि सुलेमान पिछले कई समय से न ही किसी आयोजन में दिखाई दिए और न ही उन्हें कोई प्रमुख स्थान पर दिखाई दिए। लेकिन जब सुलेमान आईएएस सर्विस मीट के मंच पर दिखाई दिए तो सभी अफसरों के बीच में चर्चा का केंद्र बन गए। अब देखने वाली बात यह है कि सुलेमान आने वाले कितने दिनों तक इस तरह से मोहन सरकार में हाशिए पर पड़े रहते हैं। चर्चा इस बात की भी है कि मोहन सरकार जल्द ही सुलेमान द्वारा रचे गए भ्रष्टाचार के तंत्र से पर्दा उठा सकते हैं।

आखिर किसी कृपा से करोड़पति बने शर्मा

मध्यप्रदेश में दो दिन पहले आयकर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही पूरे देश में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। एक छोटे से कर्मचारी के पास इतनी बड़ी संख्या में केश बरामद होने से आईएएस अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक चर्चा इस बात को लेकर है कि आखिर शर्मा के ऊपर किस महानव्यक्ति का आशीर्वाद है। आखिर कौन लोग हैं वह जो इस दिशा में कार्य कर रहे हैं और राज्य की वित्तीय व्यवस्था को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। जाहिर है कि इस पूरे मामले में कई रिटायर्ड और वर्तमान अफसरों के नाम सामने आने की आशंका है। अब देखने वाली बात यह है कि आयकर विभाग की यह कारवाही आगे कहा जाकर रुकती है।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

"लहसुन कभी 40 था,
आज 400!"

बढ़ती महंगाई ने बिगाड़ा आम आदमी की रसोई का बजट - कुंभकरण की नींद सो रही सरकार!

-राहुल गांधी
कांग्रेस नेता @RahulGandhi

मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार युवाओं को रोजगार देने के मामले में ना सिर्फ पूरी तरह नाकाम है बल्कि वह रोजगार देने के नाम पर बेरोजगारों का मजाक उड़ा रही है।

-कमलनाथ
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने अपनी कार्यशैली और सुशासन व्यवस्था से बनाई विशिष्ट पहचान

समता पाठक/जगत प्रवाह

सुशासन बाबू के नाम से प्रसिद्ध बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च, 1951 को पटना के बख्तियारपुर में हुआ था। नीतीश कुमार के पिता स्व. राम लखन सिंह जी स्वत्रंता सेनानी और विख्यात गांधीवादी नेता थे। नीतीश कुमार ने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पटना से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। नीतीश कुमार की राजनीतिक परवरिश देश के महान समाजवादी राजनेताओं के इर्द-गिर्द हुई, जिसका प्रभाव नीतीश जी के व्यक्तित्व व राजनीति पर साफ देखा जा सकता है। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, वी.पी सिंह जैसे राजनैतिक दिग्गजों की देख-रेख में नीतीश कुमार ने राजनीति के सभी दृष्टिकोणों समझा और परखा। नीतीश कुमार जी ने साल 1974 से 1977 तक चले जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। उनके अंदर समाजवाद की ऐसी छाप पड़ी उन्होंने अपने राजनीतिक सफर के लिए समाजवाद का रास्ता चुन लिया। छह कार्यकालों के लिए बरह के सांसद के रूप में भी कार्यभार संभाला। नीतीश कुमार ने राज्य में पिछले शासन के प्रदर्शन से नागरिकों की नाराजगी की अपील की। उन्होंने बिहार के राजनैतिक मैदान में कदम रखा और बिहार की बहती अर्थव्यवस्था को रोकने के लिए प्रभावी योजनाएँ तैयार कीं। अपने मंत्री पद के प्रारंभिक वर्षों में, उन्होंने 100,000 से अधिक स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति की, यह सुनिश्चित किया कि डॉक्टरों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कार्य किया, बुनियादी ढांचे का विकास किया, महिला निरक्षरता को आधे से कम कर दिया, अपराधियों पर नकेल कसकर और बिहारी की औसत आय दोगुनी करके एक अराजक राज्य को बदल दिया।

राजनीति का उगता हुआ यह सूरज साल 1985 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बिहार विधानसभा में पहुंच गया। विलक्षण राजनीतिक प्रतिभा के धनी रहे। नीतीश कुमार वर्ष 1987 में युवा लोक दल के अध्यक्ष बना दिए गए। इसके बाद वर्ष 1989 में वह बिहार में जनता दल इकाई के महासचिव और नौवीं लोकसभा के सदस्य चुने गए। लोकसभा में अपने पहले कार्यकाल में नीतीश कुमार केन्द्रीय राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गयी। वर्ष 1991 में नीतीश कुमार दोबारा लोकसभा के लिए चुने गए और साथ ही राष्ट्रीय स्तर के महासचिव बनाए गए। वे लगातार वर्ष 1989 से लेकर 2004 तक बाढ़ निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव जीतते रहे। वर्ष 2001 से 2004 के बीच कैबिनेट मंत्री के तौर पर रेल मंत्रालय जैसी जिम्मेदारी को भी बखूबी संभाला।

बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को अब तक सात बार बिहार के मुख्यमंत्री बनाया है। पहली बार मार्च 2000 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बिहार में विभिन्न क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित किया। उनके कुशल प्रशासन की वजह से आज देश उन्हें सुशासन बाबू के नाम से जानता है। देश के वरिष्ठ व कुशल नेताओं की लिस्ट में नीतीश जी का नाम प्रमुखता से दर्ज है। नीतीश कुमार को राजनीतिक शुचिता, सार्वजनिक सक्रियता व कुशल प्रशासक के लिए कई पुरुस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। जिनमें साल फ़ोर्ब्स "इंडियन पर्सन ऑफ दि इयर" अवॉर्ड, जेपी स्मारक पुरस्कार, इकोनॉमिक टाइम्स "बिजनेस रिफार्मर ऑफ दि इयर, पोलियो उन्मूलन चैम्पियनशिप अवार्ड,सफल शराबबंदी के लिए अणुव्रत सम्मान, एनडीटीवी इंडियन ऑफ दि इयर अवॉर्ड आदि हैं।

नीतीश कुमार राजनीति और समाज में एक नई सोच, नया लक्ष्य और नई कार्यप्रणाली के जीते-जागते जनक है।

विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर आयोजित किए गए कार्यक्रम

-कैलाशचंद्र जैन

जगत प्रवाह. विदिशा। पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में विश्व ध्यान दिवस के उपलक्ष्य में ध्यान शिविर आयोजित किये जाने के निर्देश प्रसारित किये गये थे। जिसके परिपालन में पुलिस अधीक्षक विदिशा रोहित काशवानी के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सिरोंज, कुरवाई, गंजबासौदा, लटेरी के मार्गदर्शन में प्रातः 08.00 बजे से 09.00 बजे के बीच ध्यान शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य कार्यक्रम जिला मुख्यालय विदिशा स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित किया गया।

ध्यान के दौरान और नियमित रूप से ध्यान करने वाले लोगों में समय के साथ रक्तचाप कम हो जाता है। इससे हृदय और रक्त वाहिकाओं पर तनाव कम हो सकता है और हृदय रोग को रोकने में मदद मिल सकती है। नियमित ध्यान चिंता को कम करने में मदद करता है। यह सामाजिक चिंता, भय और जुनूनी-बाध्यकारी व्यवहार जैसे मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों में भी मदद कर सकता है। (जगत फीचर्स)

-अमित राजपूत

जगत प्रवाह. देवरी। म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग भोपाल के निर्देशानुसार 21 दिसम्बर 2024 विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवरी में ध्यान सत्र का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. ओम प्रकाश दुबे ने ध्यान का महत्व बताते हुए तनाव मुक्ती एवं ध्यान सत्र के बारे में विद्यार्थियों को अवगत कराया। कार्यक्रम प्रभारी डॉ. अनामिका पाठक ने ध्यान की आवश्यकता को बताते हुए विद्यार्थियों को ध्यान से होने वाले लाभों की जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम के सहप्रभारी विनोद सोनी ने विद्यार्थियों को ध्यान की महत्वता एवं ध्यान क्रिया को कराया। इस अवसर पर जनभागीदारी अध्यक्ष दीपक सिंह ठाकुर, डॉ. जी.आर. चौहान, डॉ. ओमना सेनानी, श्रीमती मनीषा शर्मा, डॉ. किरण ठाकुर, डॉ. महेन्द्र चौरसिया, डॉ. आशीष कुमार जैन, डॉ. शिवेन्द्र पाठक, डॉ. रिजवान खान, डॉ. राजेन्द्र कुमार नागेश, राजेश गिरवाल, श्रीमती ज्योति तिवारी, पंकज प्रजापति, अबरार खान सहित महाविद्यालय परिवार व विद्यार्थी उपस्थित रहे। (जगत फीचर्स)

मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान के तहत डोर-टू-डोर सर्वे

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान के तहत डोर टू डोर सर्वे का कार्य चल रहा है, जिसमें भारत सरकार एवं राज्य सरकार की चिन्हित हितग्राही मूलक योजनाओ का शत-प्रतिशत योजना का लाभ छूटे हितग्राहियों को मिल सके इसलिए कमचारी अधिकारियों के द्वारा घर घर जाकर जानकारी ली जा रही है दिनांक 19/12/2024 ग्राम बोरी में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न योजनाओं राजस्व विभाग 1, महिला बाल विकास विभाग 15, विद्युत विभाग 1, खाध विभाग 12, वन विभाग 3, पंचायत विभाग 23, कषि विभाग 9, पशु विभाग 3, स्वस्थ्य विभाग 1, सामाजिक न्याय 2, स्वच्छ भारत मिशन 4,, उज्जवला योजना 2, श्रम विभाग 1 आवेदन सर्वे दल के पास प्राप्त हुए हैं। शिविर में सरपंच झुमुकलाल माको, शिविर प्रभारी डीके त्रिपाठी प्रधानमंत्री सड़क केएस कामले जनपद पंचायत टिमरनी बीके साहू दीपक पटेल पशु पालन नवीन विश्वकर्मा सचिव रामदास यादव सहायक सचिव महेश कीर सहायक सचिव टेमरु बहार उषा राजपूत, anm, स्वास्थ्य विभाग गंगा बाई सुमन बाई आंगनबाड़ी से उपस्थित रहे। (जगत फीचर्स)

एम्स भोपाल की डॉ. रागिनी श्रीवास्तव ने हेल्थकेयर में एआई की भूमिका पर मैनिट में दिया व्याख्यान

-अर्चना शर्मा

जगत प्रवाह. भोपाल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के मार्गदर्शन में संकाय सदस्य शैक्षणिक और शोध गतिविधियों में लगातार योगदान दे रहे हैं। हाल ही में, फिजियोलॉजी विभाग की डॉ. रागिनी श्रीवास्तव ने मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (मैनिट), भोपाल में एक व्याख्यान दिया।

शिष्टाचार की समस्त विधाओं में सबसे महत्वपूर्ण यातायात शिष्टाचार है: डीएसपी संतोष मिश्रा

-नरेन्द्र दीक्षित

जगत प्रवाह. नर्मदापुरम। सर्वाइट स्कूल में चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के दौरान उक्त संदेश उप पुलिस अधीक्षक यातायात संतोष मिश्रा ने शिक्षकों और छात्रों को दिया। उल्लेखनीय है कि पुलिस मुख्यालय के आदेश पालन में यातायात, साइबर और नशामुक्ति अभियान के अंतर्गत आज सर्वाइट स्कूल नर्मदापुरम में यातायात पुलिस द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्कूलों में जागरूकता अभियान की आवश्यकता और कार्यक्रम की रूपरेखा से छात्र छात्राओं को अवगत कराया एवं हेलमेट और सीट बेल्ट की आवश्यकता पर प्रकाश डाला मुख्य उदबोधन उप पुलिस अधीक्षक यातायात संतोष मिश्रा ने दिया, जिसमें पीपीटी के माध्यम से मुख्य नियम, सड़क पर चलने, पार करने, दोपहिया वाहन चलाते समय ध्यान केंद्रित करने वाले बिंदुओं के संबंध में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि "स्कूल और घरों में बच्चों को हम विभिन्न शिष्टाचार की शिक्षा देते हैं लेकिन इन शिष्टाचार से भी महत्वपूर्ण यातायात शिष्टाचार है, क्योंकि दूसरे शिष्टाचारों की त्रुटि में हमें सुधार करने का अवसर मिलता है लेकिन याता यात शिष्टाचार की अनदेखी जानलेवा हो सकती है और हो सकता है कि फिर सुधार का अवसर न मिले इसलिए इस शिष्टाचार को जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाए। यातायात नियमों के अतिरिक्त साईबर फ्राड के तरीकों और बचाव के संबंध में जागरुक करते हुए लालच से बचने और अनजान लिंक न खोलने, ओटीपी शेयर न करने और डिजिटल अरेस्ट जैसे फर्जीवाड़े के संबंध में जानकारी दी गई।जागरूकता कार्यक्रम के दौरान संस्थान की प्रिंसिपल सलूजा मेम उपस्थित रहीं ।कार्यक्रम के दौरान मंच का कुशल संचालन समृद्धि राव, अवनि चौरे, अश्विनी चौहान, सुहानी सोनी, अदिति रंजन और वंशिका चौकसे ने किया। (जगत फीचर्स)

प्रधानमंत्री ने नदी जोड़ो परियोजना के तहत तीन नदियों को जोड़ने की आधारशिला रखी

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

मध्यप्रदेश और राजस्थान के बीच पार्वती, कालीसिंध और चंबल का पानी एक बड़े जलस्रोत के रूप में बहता है। मध्यप्रदेश में केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की शुरूआत के बाद अब उपरोक्त नदियों को जोड़े जाने की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में रख दी है। इसके प्रतीक स्वरूप तीनों नदियों के पानी को एक घड़े में भरा गया। तत्पश्चात भारत सरकार और राजस्थान एवं मध्यप्रदेश राज्य सरकारों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। 72000 करोड़ रुपए इस परियोजना पर खर्च होंगे। इसमें 90 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार देगी। इस राशि में से 35000 करोड़ रुपए मध्यप्रदेश और 37000 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार खर्च करेगी। इसमें मध्यप्रदेश के 13 जिलों के 3217 ग्रामों की सूरत बदल जाएगी। दोनों प्रदेशों में मिलाकर 27 नए बांध बनेंगे और 4 पुराने बांधों पर नहरों की जलग्रहण क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसी के साथ 64 साल पुरानी ग्वालियर-चंबल संभाग की चंबल-नहर प्रणाली का उद्धार नए तरीके से किया जाएगा। तय है, ये नदियां निर्धारित अवधि में जुड़ जाती हैं, तो सिंचाई के लिए कृषि भूमि का रकबा बढ़ने के साथ अन्न की पैदावार बढ़ेगी। किसान खुशहाल होंगे और उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा।

नदियों की धारा मोड़ने का दुनिया में पहला उदाहरण ऋग्वेद में मिलता है। इंद्र ने सिंचाई और पेयजल की सुविधा सुगम कराने की दृष्टि से सिंधु नदी की धारा को मोड़ा था। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी की धारा को पहाड़ तोड़कर भगवान परशुराम ने मोड़ा था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपयी ने नदी जोड़ो अभियान की जो परिकल्पना की थी, उसे नरेंद्र मोदी ने साकार करने की शुरूआत केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के साथ कर दी थी। ये परियोजनाएं जल-शक्ति अभियान 'कैच द रन' के तहत अमल में लाई जा रही हैं। बाढ़ और सूखे से परेशान देष

नदियां लिखेंगी विकास की गाथा

में नदियों के संगम की परियोजना मूर्त रूप ले रही हैं, यह देशवासियों के लिए प्रसन्नता की बात है। इन परियोजनाओं को जोड़ने का अभियान सफल होता है तो भविष्य में 57 अन्य नदियों के मिलन का रास्ता खुल जाएगा। दरअसल बढ़ते वैश्विक तापमान, जलवायु परिवर्तन और बदलते वर्षा-चक्र के चलते जरूरी हो गया है कि नदियों के बाढ़ के पानी को इकट्ठा किया जाए और फिर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में नहरों के जरिए भेजा जाए। ऐसा संभव हो जाता है तो पेयजल की समस्या का निदान तो होगा ही, सिंचाई के लिए भी किसानों को पर्याप्त जल मिलने लग जाएगा। वैसे भी भारत में विष्व की कुल आबादी के करीब 18 प्रतिषत लोग रहते हैं और उपयोगी जल की उपलब्धता महज 4 प्रतिशत है। हालांकि पर्यावरणविद् इन परियोजनाओं को यह कहकर विरोध कर रहे हैं कि नदियों को जोड़ने से इनकी अविरलता खत्म होगी, नतीजतन नदियों के विलुप्त होने का संकट बढ़ जाएगा।

कृत्रिम रूप से जीवनदायी नर्मदा और मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदियों को जोड़ने का काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही कर चुके थे। चूंकि ये दोनों नदियां मध्य-प्रदेश में बहती थीं, इसलिए इन्हें जोड़ा जाना संभव हो गया था। केन और बेतवा नदियों को जोड़ने की तैयारी में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश् की सरकारें बहुत पहले से जुटी थीं। इस परियोजना को वर्ष 2005 में मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन पानी के बंटवारे को लेकर विवाद बना हुआ था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों राज्यों में अलग-अलग दलों की सरकारें होने के कारण एकमत नहीं हुई। कालांतर में केंद्र समेत उप्र और मप्र में भी भाजपा की सरकारें बन गईं। नतीजतन परियोजनाओं पर सहमति बन गई। केन नदी जबलपुर के पास कैमूर की पहाड़ियों से निकलकर 427 किमी उत्तर की और बहने के बाद बांदा जिले में यमुना नदी में जाकर गिरती है। वहीं बेतवा नदी मध्यप्रदेश के रायसेन जिले से निकलकर 576 किमी बहने के बाद उत्तरप्रदेश के हमीरपुर में यमुना में मिलती है। केन-बेतवा नदी जोड़ो योजना पर भूमि अधिग्रहण के साथ तेज गति से बांधों एवं नहरों का काम षुरू हो गया है।

जीवनदायी नदियां हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। नदियों के किनारे ही ऐसी आधुनिकतम बढ़ी सभ्यताएं विकसित हुईं, जिन पर हम गर्व कर सकते हैं। सिंधु घाटी और सारस्वत (सरस्वती) सभ्यताएं इसके उदाहरण हैं। भारत के सांस्कृतिक उन्नयन के नायकों में भागीरथी, राम और कृष्ण का नदियों से गहरा संबंध रहा है। भारतीय वांगमय में इंद्र और कुबेर विपुल जलराशि के प्राचीनतम वैज्ञानिक-प्रबंधक रहे हैं। भारत भूखण्ड में आग, हवा और पानी को सर्वसुलभ नियामत माना गया है। हवा और पानी की शुद्धता और सहज उपलब्धता नदियों से है। दुनिया के महासागरों, हिमखण्डों, नदियों और बड़े जलाशयों में अकूत जल भण्डार हैं। लेकिन मानव के लिए उपयोग जीवनदायी जल और बढ़ती आबादी के लिए जल की उपलब्धता का बिगड़ता अनुपात चिंता का बड़ा कारण बना हुआ है। ऐसे में भी बढ़ते तापमान के कारण हिमखण्डों के पिघलने और अवर्षा के चलते जल स्त्रोतों के सूखने का सिलसिला जारी है। वर्तमान में जल की खपत कृषि, उद्योग, विद्युत और पेयजल के रूप में सर्वाधिक हो रही है। हालांकि पेयजल की खपत मात्र आठ फीसदी है। जिसका मुख्य स्त्रोत नदियां और भू-जल हैं। औद्योगिकिकरण, शहरीकरण और बढ़ती आबादी के दबाव के चलते एक ओर नदियां सिकुड़ रही हैं, वहीं औद्योगिक कचरा और मल मूत्र बहाने का सिलसिला जारी रहने से गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां इतनी प्रदूषित हो गईं हैं कि यमुना नदी को तो एक पर्यावरण संस्था ने मरी हुई नदी तक घोषित कर दिया है।

प्रस्तावित करीब 120 अरब डालर अनुमानित खर्च की नदी जोड़ों परियोजना को दो हिस्सों में बांटकर अमल में लाया जाएगा। एक प्रायद्वीप स्थित नदियों को जोड़ना और दूसरे, हिमालय से निकली नदियों को जोड़ना। प्रायद्वीप भाग में 16 नदियां हैं, जिन्हें दक्षिण जल क्षेत्र बनाकर जोड़ा जाना है। इसमें महानदी, गोदावरी, पेन्नार, कृष्णा, पार, तापी, नर्मदा, दमनगंगा, पिंजाल और कावेरी को जोड़ा जाएगा। पशिचम के तटीय हिस्से में बहने वाली नदियों को पूर्व की ओर मोड़ा जाएगा। इस तट से जुड़ी तापी नदी के दक्षिण भाग को मुंबई के उत्तरी भाग की नदियों से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। केरल और कर्नाटक की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की जलधारा पूर्व दिशा में मोड़ी जाएगी। यमुना और दक्षिण की सहायक नदियों को भी आपस में जोड़ा जाना इस परियोजना का हिस्सा है। हिमालय क्षेत्र की नदियों के अतिरिक्त जल को संग्रह करने की दृष्टि से भारत और नेपाल में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों पर विशाल जलाशय बनाने के प्रावधान हैं। ताकि वर्षाजल इकट्ठा हो और उत्तरप्रदेश, बिहार एवं असम को भंयकर बाढ़ का सामना करने से छुटकारा मिले। इन जलाशयों से बिजली भी उत्पादित की जाएगी। इसी क्षेत्र में कोसी, घांघरा, मेच, गंड़क, साबरमती, शारदा, फरक्का, सुन्दरवन, स्वर्णरेखा और दमोदर नदियों को गंगा, यमुना और महानदी से जोड़ा जाएगा। करीब 13,500 किमी लंबी ये नदियां भारत के संपूर्ण मैदानी क्षेत्रों में अठखेलियां करती हुई मनुष्य और जीव जगत के लिए प्रकृति का अनूठा और बहुमूल्य वरदान बनी हुई हैं। 2528 लाख हैक्टेयर भू-खण्डों और वनप्रांतरों में प्रवाहित इन नदियों में प्रति व्यक्ति 690 घनमीटर जल है। कृषि योग्य कुल 1411 लाख हेक्टेयर भूमि में से 546 लाख हेक्टेयर भूमि इन्हीं नदियों की बदौलत प्रति वर्ष सिंचित की जाकर फसलों को लहलहाती हैं।

दरअसल बढ़ते वैष्विक तापमान, जलवायु परिवर्तन, अलनीनो और बदलते वर्षा चक्र के चलते जरूरी हो गया है कि नदियों के बाढ़ के पानी को इकट्ठा किया जाए और फिर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में नहरों के जरिए भेजा जाए। ऐसा संभव हो जाता है तो पेयजल की समस्या का निदान तो होगा ही, सिंचाई के लिए भी किसानों को पर्याप्त जल मिलने लग जाएगा। वैसे भी भारत में विष्व की कुल आबादी के करीब 18 प्रतिशत लोग रहते हैं और उपयोगी जल की उपलब्धता महज 4 प्रतिशत है। इसलिए नदी जोड़ो परियोजनाओं को भविष्य के लिए लाभदायी माना जा रहा है।

स्वच्छ भारत मिशन: शहरी कचड़ा प्रबंधन का ब्लू प्रिंट

पर्यावरण की फिक्र
डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद्

हमारा देश स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) की दसवीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। एक ऐसा मिशन जिसने भारत में स्वच्छता और सफाई के नए पैमाने स्थापित कर एक नई परिभाषा गढ़ी है। स्वच्छ भारत मिशन की संकल्पना भारत की जनता के सामने न केवल एक स्वच्छ और सुंदर भारत का सपना प्रस्तुत करती है, बल्कि यह हमें कचरा प्रबंधन जैसे बुनियादी मुद्दों की ओर भी सोचने पर मजबूर करती है। इस मिशन का उद्देश्य एक ऐसा रोडमैप तैयार करना है जो पर्यावरणीय चुनौतियों का हल निकाले और कचरा प्रबंधन को न केवल सरकारी जिम्मेदारी बल्कि हर नागरिक का दायित्व बनाए। आज जब भारत के शहर और गांव कचरे के ढेर से जूझ रहे हैं, तब यह मिशन एक उम्मीद की किरण बनकर उभरा है।

2 अक्टूबर 2014 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की, तब इसका मुख्य लक्ष्य देश को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) बनाना और स्वच्छता की संस्कृति को जन-जन तक पहुँचाना था। मिशन के पहले चरण में शौचालय निर्माण और स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने का काम किया गया। इसके बाद मिशन का दूसरा चरण कचरा प्रबंधन और सस्टेनेबल स्वच्छता पर केंद्रित है। कचरा प्रबंधन की समस्या शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के साथ और भी गंभीर होती जा रही है। तेजी से बढ़ते शहरों में जनसंख्या और कचरे का उत्पादन दोनों ही बढ़े हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हर दिन लगभग 1.5 लाख टन ठोस कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें से केवल 70-75% ही एकत्रित हो पाता है और लगभग 20-25% ही पुनः चक्रित (रीसाइकल) किया जाता है। शेष कचरा लैंडफिल्स में चला जाता है या अव्यवस्थित ढंग से नष्ट कर दिया जाता है, जिससे पर्यावरणीय समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक और बायोमेडिकल कचरे की मात्रा ने प्रबंधन को कठिन बना दिया है। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बढ़ती खपत के कारण कचरे का स्वरूप भी जटिल हो गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस कचरे के साथ-साथ जैविक कचरे का भी प्रबंधन चुनौतीपूर्ण है। उचित कचरा निस्तारण की कमी के कारण खेतों में और जल स्रोतों में कचरा फेंका जा रहा है, जिससे भूमि और जल प्रदूषण बढ़ रहा है।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत कचरा प्रबंधन को कारगर बनाने के लिए एक व्यापक ब्लू प्रिंट तैयार किया गया है। इस ब्लू प्रिंट के तीन मुख्य स्तंभ हैं– जागरूकता, पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) और प्रौद्योगिकी का उपयोग।

कचरा प्रबंधन की सफलता के लिए जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण है। सोर्स सेग्रीगेशन (कचरे का स्रोत पर ही वर्गीकरण) मिशन के तहत यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है कि लोग कचरे को घरों, कार्यालयों और संस्थानों में ही अलग-अलग करें– जैविक कचरा (गीला कचरा) और अजैविक कचरा (सूखा कचरा)। हरे और नीले रंग के डस्टबिन के माध्यम से कचरे के वर्गीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्कूली बच्चों, महिलाओं और सामुदायिक समूहों के माध्यम से "स्वच्छता ही सेवा" जैसे अभियानों को बढ़ावा दिया जा रहा है। समाज के प्रभावशाली लोगों और सेलिब्रिटीज के माध्यम से जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है।

स्वच्छ भारत मिशन का एक मुख्य उद्देश्य "कचरे को संसाधन" में बदलना है। शहरों और कस्बों में ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्रों की स्थापना की जा रही है, जहाँ कचरे को रीसाइकिल किया जा सके। गीले कचरे को खाद बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। "कम्पोस्टिंग एट होम" जैसे अभियानों के माध्यम से लोगों को अपने घरों में ही कचरे से जैविक खाद तैयार करने की शिक्षा दी जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक कचरे (ई-वेस्ट) के प्रबंधन के लिए भी विशेष योजनाएँ बनाई गई हैं। निर्माता कंपनियों को "Extended Producer Responsibility (EPR)" के तहत जिम्मेदार बनाया जा रहा है। कचरा प्रबंधन में आधुनिक तकनीक का उपयोग गेम-चेंजर साबित हो रहा है।कई शहरों में स्मार्ट डस्टबिन लगाए जा रहे हैं, जो भरे जाने पर स्वचालित रूप से सफाई कर्मियों को सूचित करते हैं। इसके अलावा, मोबाइल ऐप्स के माध्यम से शिकायत दर्ज करने और कचरा संग्रहण की निगरानी को आसान बनाया गया है। ठोस कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने वाले संयंत्रों की स्थापना की जा रही है। ये प्लांट कचरे का निस्तारण करने के साथ-साथ ऊर्जा उत्पादन में भी योगदान देते हैं। पुराने कचरा ढेरों (लैंडफिल्स) को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट किया जा रहा है।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत कई सफलताएँ मिली हैं। कई शहर ओडीएफ घोषित किए गए हैं। कचरा वर्गीकरण का प्रतिशत बढ़ा है। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के तहत कई शहरों में कचरा प्रबंधन तकनीकों का विकास हुआ है। हालांकि, अभी भी कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं। जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण के कारण कचरे का बढ़ता उत्पादन। ग्रामीण इलाकों में अव्यवस्थित कचरा निस्तारण। सिंगल यूज प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग।

सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। कचरा प्रबंधन को लेकर स्वच्छ भारत मिशन के ब्लू प्रिंट को सफल बनाने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। सरकार, स्थानीय निकायों और आम जनता को एक साथ आना होगा। कचरा प्रबंधन को लेकर सख्त नियम लागू करने की आवश्यकता है।

निजी कंपनियों और स्टार्टअप्स को इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। स्वच्छ भारत 2.0 मिशन के दूसरे चरण में ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों में कचरा प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका निष्कर्ष है स्वच्छ भारत मिशन केवल एक अभियान नहीं है, बल्कि यह एक जनांदोलन है। यह न केवल स्वच्छता को बढ़ावा देता है, बल्कि स्वास्थ्य, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। कचरा प्रबंधन का यह ब्लू प्रिंट यदि सही तरीके से लागू किया जाए, तो भारत एक स्वच्छ और स्वस्थ देश बनने की ओर अग्रसर होगा। आइए, हम सभी इस मिशन में भागीदार बनें और कचरा मुक्त भारत के सपने को साकार करें। स्वच्छता की यह यात्रा तभी पूरी होगी जब हर नागरिक इस जिम्मेदारी को समझेगा और स्वच्छ भारत का सिपाही बनेगा।

दया, प्रेम और शांति की प्रेरणा है क्रिसमस

आज की बात
प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

"प्रभु यीशु ने जो कहा उसका संकलन बाइबिल में है लेकिन उन्होंने जो जीवन जिया उसका संकलन मानवता की स्मृतियों में है"

25 दिसंबर को पूरे विश्व में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाएगा। ईसा मसीह का जीवन दया, प्रेम और शांति का संदेश देता है। प्रभु यीशु ने जो कहा उसका संकलन बाइबिल में है लेकिन उन्होंने जो जीवन जिया उसका संकलन मानवता की स्मृतियों में है। इसलिए यह त्यौहार धर्म की सीमाओं को पार कर मानवता को एक सूत्र में बांधता है। भारत की संस्कृति अद्वैतवाद की संस्कृति है। ऐसे में भारत में क्रिसमस पर्व सांस्कृतिक एकता को दर्शाता है। रोमन साम्राज्य की रक्त पिपासा के बीच जीसस शांतिदूत बनकर पृथ्वी पर आए। दिशाहीन मानवता को उन्होंने एक

दिशा प्रदान की। भटके हुए लोगों को सही राह दिखाई और इंसानियत के लिए ही अपना बलिदान दिया। क्रिसमस भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रकटन है। धर्म, जाति और संप्रदाय से परे सभी लोग मिलकर इस त्योहार को मनाते हैं। यदि हम भारतीय वांग्मय में देखें तो अद्वैत की परिकल्पना सर्वश्रेष्ठ है। जब ईश्वर की प्रार्थना एकाकार होकर की जाए तो वह अद्वैत ही होता है। इसलिए ईशा का जन्म भले ही यरूशलम की धरती पर हुआ हो लेकिन वह भारत भूमि में भी उतने ही पूज्यनीय और मान्य हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां सभी धर्मों के बीच सांस्कृतिक एकता है और सांस्कृतिक प्रेम भी है। भारत भूमि पर अनेक धर्मों का जन्म हुआ किंतु जो धर्म भारत में नहीं जन्मे उन धर्मों को भी यहां सम्मान मिलता है। इसलिए क्रिसमस भी भारत की सांस्कृतिक एकता से जुड़ा हुआ है।

आइए, क्रिसमस से जुड़ी कुछ प्रेरक बातों पर नजर डालते हैं

1. दया का भाव जगाएं - क्रिसमस हमें दूसरों की मदद करने और उन्हें खुश करने का मौका देता है। चाहे वह किसी जरूरतमंद को दान देना हो या किसी की मदद करना हो, हर छोटा कदम मायने रखता है। अपने समुदाय में स्वयंसेवा करके आप न केवल दूसरों की मदद कर सकते हैं बल्कि खुद को भी संतुष्टि महसूस करेंगे।

2. रिश्तों को मजबूत बनाएं - क्रिसमस का त्योहार परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का एक शानदार अवसर है। आप एक साथ समय बिताकर अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। अपने प्रियजनों के साथ हंसी-मजाक और यादें बनाएं। यह आपको खुश रखने के साथ-साथ आपके रिश्तों को भी मजबूत बनाएगा।

3. आभार व्यक्त करें- इस त्योहार पर अपने जीवन में मौजूद सभी अच्छी चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। यह आपको सकारात्मक रहने में मदद करेगा।

4. आशा और विश्वास रखें- क्रिसमस हमें उम्मीद और विश्वास की भावना से भर देता है। भविष्य के लिए सकारात्मक सोचें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। आप अपने जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए प्रयास करें।

5. अपने अंदर के बच्चे को जगाएं- क्रिसमस हमें अपने अंदर के बच्चे को जगाने और जीवन का आनंद लेने का मौका देता है। दोस्तों और परिवार के साथ खेलें और मजे करें। यह आपको तनाव मुक्त रखने में मदद करेगा।

क्रिसमस का त्योहार सिर्फ उपहारों, सजावट और पार्टियों से कहीं ज्यादा है। यह एक ऐसा समय है जब हम प्यार, दया और शांति की भावनाओं को अपने जीवन में शामिल करते हैं। आइए, हम सभी मिलकर इस त्योहार को यादगार बनाएं और दूसरों के लिए कुछ अच्छा करें।

सांता क्लॉजः सिर्फ एक किरदार नहीं, एक प्रेरणा भी हैं

सांता क्लॉज का नाम सुनते ही हमारे मन में एक मोटे, हंसमुख व्यक्ति की छवि उभर आती है, जो लाल रंग का कोट पहनकर उड़ने वाले हिरनों की गाड़ी में सवार होकर बच्चों को उपहार देता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि सांता क्लॉज सिर्फ एक किरदार नहीं, बल्कि एक प्रेरणा भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि सांता का असली नाम संत निकोलस था। संत निकोलस का जन्म जीसस की मौत के करीब 280 साल बाद हुआ था। उन्होंने अपना पूरा जीवन ईश्वर की भक्ति, प्रेम और शांति का संदेश देने के साथ दूसरों को खुशियों बांटने में लगा दिया। तब से वे सभी के लिए एक प्रेरणा बन गए और उनकी याद में लोग उनके जैसी वेशभूषा धारण कर दूसरों को खुशियां बांटने का प्रयास करते हैं

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। संपादक : विजया पाठक। RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)